कृष्णा भट्टाचार्य

बनाम

सारथी चौधरी और अन्य

(सिविल अपील सं. 1545/2015)

20 नवंबर,2015

बेंच: दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत, जेजे।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उपधारा 2 (ए), 3 (iv) और 12- पत्नी द्वारा धारा 12 के अंतर्गत आवेदन अंतर्गत- - पति के कब्जे में स्त्रीधन वस्तुओं को जब्त करने की मांग-इस आधार पर आवेदन खारिज किया गया कि पत्नी धारा 2(a) के तहत ' व्यथित व्यक्ति नहीं रही क्योंकि पक्षकार न्यायिक रूप से पृथक हो चुके थे और यह कि आवेदन मियाद बाहर का होने से वर्जित था - इस आदेश को सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अधिनियम एक कानून है जो संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों को दी गई गारंटी की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है, न्यायालय से और अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपेक्षित है- अधिनियम के तहत याचिका को वैधानिकता के आधार पर खारिज करने से पहले जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर गहन विचार-विमर्श होना चाहिए। -वर्तमान मामले में, आवेदक-पत्नी धारा 2 (a) के तहत एक 'पीड़ित व्यक्ति' का दर्जा समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद भी पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति छीनी नहीं जा सकती -पति द्वारा स्त्रीधन को अपने कब्जे में बनाए रखना एक निरंतर अपराध है-जब तक वैवाहिक स्थिति बनी रहती है और स्त्रीधन पति के कब्जे में रहता है, तब तक पत्नी हमेशा धारा 12 के तहत

अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है- ऐसे आवेदन को मियाद के आधार पर वर्जित नहीं किया जा सकता है।

वैवाहिक कानून-'तलाक' और 'न्यायिक पृथक्करण - के बीच अंतर।

शब्द और वाक्यांशः ' स्त्रीधन'-का अर्थ, वैवाहिक कानून के संदर्भ में

अपील को स्वीकारते हुए, न्यायालय ने अभिनर्धारित किया:

1॰ संविधान के तहत महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 का अधिनियम बनाया गया है–
होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों की शिकार होती हैं। 2005 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम है। 2005 अधिनियम का शब्दकोश खंड व्यापक दायरे में है। "घरेलू हिंसा" की परिभाषा में हिंसा की एक श्रृंखला शामिल है जो "आर्थिक दुरुपयोग" अपने दायरे में लेता है और "आर्थिक दुरुपयोग" शब्द के कई पहलू हैं: [पैरा 3] [70-ई-जी]

2. विधान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अदालतों से अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण की उम्मीद है, जहां 2005 के अधिनियम के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती है, वह कभी भी कल्पना नहीं की जानी चाहिए लेकिन, याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज करने से पहले याचिका में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर एक उपयुक्त और गहन चर्चा होनी चाहिए। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अदालत को सभी कोणों से तथ्यों की जांच करेगी कि क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में कि गई शिकायत को रद्द करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलें वास्तव में कानूनी रूप से सही है व सत्य हैं। किसी याचिका को मियाद के आधार पर खारिज करने से पहले, यह देखना अनिवार्य है कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पीड़ित वह गैर क्षेत्राधिकार कि परिस्थिति का सामना नहीं करे, चूंकि 2005 का अधिनियम

फायदेमंद होने के साथ-साथ महिलाओं के संवैधानिक अधिकार की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से सकारात्मक अधिनियम है और यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी भी प्रकार के घरेलू हिंसा की शिकार नहीं बने। [पैरा 4] [70-एच; 71-ए-बी, बी-सी, डी-ई]

3. किसी तलाक की डिक्री और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के मध्य अंतर है; पहले वाले में, अवस्था का विच्छेद होता है और पक्षकार पति और पत्नी नहीं रहते हैं, जबकि बाद वाले में, पति और पत्नी के बीच संबंध जारी रहते है और विधिक संबंध जारी रहते है क्योंकि इन्हें छिना नहीं गया है। इस प्रकार समझा गया कि, नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिस पर उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है कि पक्षकार न्यायिक रूप से अलग हो गए हैं, अतः अपीलार्थी पत्नी "पीड़ित व्यक्ति" नहीं रही है, पूरी तरह से अपोषणीय है। [पैरा 22] [84 - ए-सी]

हीराचंद श्रीनिवास मनगांवकर बनाम सुनंदा (2001) 4 एससीसी 125: 2001 (2) एससीआर 491-निर्भर रहा गया।

जीत सिंह व अन्य बनाम यू. पी. राज्य व अन्य (1993) 1 एससीसी 325: 1992 (3) पूरक एससीआर 246; बाई मणि बनाम जयंतीलाल दह्याभाई एआईआर 1979 गुज 209; सौन्दराम माल बनाम सुंदरा महालिंगा नादर एआईआर 1980 मद्रास 294-संदर्भित।

"हिंदू लॉ ऑफ मैरिज और स्त्रीधन" सर गुरुदास द्वारा - संदर्भित।

4. जब तक पीड़ित व्यक्ति का दर्जा कायम है और स्त्रीधन पति के कब्जे में है, पत्नी अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत हमेशा अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं क्योंकि विवाह विच्छेद की डिक्री के कारण पक्षकारों का दर्जा समाप्त नहीं होता है। "निरंतर अपराध" की अवधारणा स्त्रीधन से वंचित होने की तारीख से लागू होता है, न तो पति के लिए और न ही कोई अन्य परिवार का सदस्य का स्त्रीधन पर कोई भी

अधिकार हो सकता है और वे मात्र स्त्रीधन के संरक्षक हैं। 2005 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पत्नी संरक्षण अधिकारी के समक्ष 2005 के अधिनियम के तहत एक या अधिक उपचार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। वर्तमान मामले में, पत्नी ने दिनांक 22.05.2010 को आवेदन प्रस्तुत किया था और उक्त प्राधिकारी ने 01.06.2010 को अग्रेषित किया था। आवेदन में पत्नी ने उल्लेख किया था कि पति ने जनवरी 2010 से मासिक भरण पोषण का भुगतान करना बंद कर दिया था, और इसलिए, उसे स्त्रीधन प्राप्त करने के लिए यह आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। "निरंतर अपराध" कि उक्त अवधारणा को और की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन मियाद द्वारा वर्जित नहीं था और निचली अदालत के साथ-साथ ही उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को मियाद द्वारा वर्जित निर्धारित कर खारिज करने में गंभीर त्रुटि कि है। [पैरा 31] [90-ए-ई]

बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी (1972) 2 एससीसी 890 : 1973 (3) एस. सी. आर. 1004- पर निर्भर।

इंदरजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य (2011) 12 एससीसी 588: 2011 (10) एससीआर 557; वी. डी. भनोट बनाम सविता भनोट (2012) 3 एस. सी. सी. 183: 2012 (1) एससीआर 867 ; सरस्वती वी. बाबू (2014) 3 एससीसी 712: 2013 (12) एस. सी. आर. 914; डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चैयाम्मल (2010) 10 एस. सी. सी. 469: 2010 (13) एस. सी. आर. 706; सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 636: 2005 (2) एससीआर 638; प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार व अन्य (1983) 2 एससीसी 370: 1985 (3) एससीआर 191: रश्मि कुमार (श्रीमती) बनाम महेश कुमार बड़ा (1997) 2 एस. सी. सी. 397 : 1996 (10) पूरक एस. सी. आर. 347; राजा बहादुर सिंह बनाम भविष्य निधि निरीक्षक और अन्य। (1984) 4 एससीसी 222: 1985 (1) एस. सी. आर. 626-संदर्भित।

"हिंदू कानून" एन. आर. राघवचारियार और मेन द्वारा" हिंदू कानून पर ग्रंथ" संदर्भित किया गया।

नज़ीरें जो संदर्भित की गई-

2011 (10) एससीआर 557	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
2012 (1) एससीआर 867	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
2013(12) एससीआर 914	संदर्भित किया गया है	पैरा 14
2010 (13) एससीआर 706	संदर्भित किया गया है	पैरा 15
2005 (2) एससीआर 638	संदर्भित किया गया है	पैरा 15
1992(3) पूरक एस.सी.आर. 246	संदर्भित	पैरा 17
2001 (2) एससीआर 491	भरोसा किया गया	पैरा 19
ए. आई. आर. 1979 गुज 209	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
ए. आई. आर. 1980 मद्रास 295	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
1985 (3) एससीआर 191	संदर्भित किया गया है	पैरा 24
1996(10)पूरक एस.सी.आर.347	संदर्भित किया गया	पैरा 26
1985 (1) एससीआर 626	भरोसा किया गया	पैरा 28
1973 (3) एससीआर 1004	भरोसा किया गया	पैरा 28

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1545/2015

त्रिपुरा उच्च न्यायालय, अगरतला के आपराधिक रिविज़न संख्या 19/2014 में दिनांक 26.08.2014 को किए गए निर्णय और आदेश से

श्री पीयूष के. रॉय, सुश्री काकली रॉय (राजन के.चौरसिया) अपीलार्थी के लिए।

मनोज, सुश्री अपर्णा सिन्हा (अभिजात पी. मेध के लिए), सुश्री एन. एस. नीप्पिनाई, ऋतुराज बिस्वास (गोपाल सिंह के लिए) प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. सुनाया गया।

1: अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता, जो यहां पहला प्रतिवादी है, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पति से अपना स्त्रीधन वापस पाने की लड़ाई इस आधार पर हारने पर कि दावा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'अधिनियम 2005') की धारा 12 के तहत पोषणीय नहीं था क्योंकि वह अधिनियम 2005 की धारा 2 (ए) के तहत एक "पीड़ित व्यक्ति" नहीं रह गई थी और इसके अलावा जो दावा किया गया था वह मियाद बाहर का होने से वर्जित था; विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत थे, अपीलकर्ता अपने वैध दावे को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी, और बार-बार असफल होने के बावजूद, उसने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 19/2014 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय, अगरतला का दरवाजा इस आशा के साथ खटखटाया कि वह अपनी संपत्ति पाने के युद्ध में विजयी होगी, लेकिन उच्च न्यायालय ने, जैसा कि स्पष्ट है, बिना अधिक विश्लेषण के, संभवतः यह सोचते हुये कि तर्क की कमी एक शानदार समझ के बराबर है, सरलता के साथ एक आदेश पारित करके हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जिसने व्यथित और परेशान पत्नी को विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया।

3. इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यों के वर्णन से पहले, हम बता सकते हैं कि संविधान के तहत महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 का अधिनियम बनाया गया है–

होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों की शिकार होती हैं। 2005 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम है। 2005 अधिनियम का शब्दकोश खंड व्यापक दायरे में है। "घरेलू हिंसा" की परिभाषा में हिंसा की एक श्रृंखला शामिल है जो "आर्थिक दुरुपयोग" अपने दायरे में लेता है और "आर्थिक दुरुपयोग" शब्द के कई पहलू हैं।

4. कानून की प्रकृति के संबंध में, अदालतों से अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है जहां 2005 के अधिनियम के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसकी कल्पना कभी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन किसी याचिका को खारिज करने से पहले भरण पोषण के लिए, उठाए गए मुद्दों पर उचित चर्चा और गहन विचार-विमर्श होना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम 2005 के तहत असहाय और असहाय "पीड़ित व्यक्ति" बाध्यकारी परिस्थितियों में अदालत का दरवाजा खटखटाता है। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह सभी पहलुओं से तथ्यों की जांच करे कि क्या प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को रद्द करने के लिए दी गई याचिका वास्तव में कानूनी रूप से सही और सत्य है। "न्याय जो किसी उद्देश्य कि प्राप्ति के लिए हे, समुद्र के नमक के बराबर है" सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कानून की अदालत उस सच्चाई को बरकरार रखने के लिए बाध्य है जो न्याय मिलने पर चमकती है। किसी याचिका को दहलीज पर फेंकने से पहले, यह देखना अनिवार्य है कि इस तरह के कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति को गैर-निर्णय की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि 2005 का अधिनियम जैसा कि हमने कहा है, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक लाभकारी और साथ ही दृढ़ता से सकारात्मक अधिनियम है, जो यह सुनिश्चित करता हे कि महिलाएं किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का शिकार न बनें।

5. वर्तमान प्रकरण में तथ्यों इस प्रकार से हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच 27.11.2005 को विवाह सम्पन्न हुआ था और वे पति-पत्नी के रूप में रहे। जैसे-जैसे आरोप बढ़ते गए, पति सहित उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर अपीलकर्ता को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि, मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पति-पत्नी दो महीने तक किराए के मकान में रहे। समय बीतने के साथ, पति ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष न्यायिक पृथक्करण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अंततः पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। न्यायिक पृथक्करण के बाद, दिनांक 22.5.2010 को अपीलकर्ता ने बाल विकास संरक्षण अधिकारी (सीडीपीओ), कार्यालय जिला निरीक्षक, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा, एडी नगर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट के समक्ष अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर कर अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सहायता की मांग की। उसने पति के कब्जे से स्त्रीधन की वस्तुएँ जब्त करने की मांग की। सीडीपीओ के समक्ष जो आवेदन किया गया था, उसे उक्त प्राधिकारी द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगरतला सदर, पश्चिम त्रिपुरा को पत्र दिनांक 1.6.2010 द्वारा भेज दिया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जिसने 14.2.2011 को अपनी लिखित आपत्तियाँ दायर कीं।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि पत्नी द्वारा दिया गया आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था और वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक पृथक्करण के आदेश के बाद स्त्रीधन के संबंध में दावा नहीं कर सकती थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता ने विवाह किया था, उसे एक "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में माना, लेकिन तय किया कि अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित कोई "घरेलू संबंध"

मौजूद नहीं था। पक्ष और इसलिए, पत्नी 2005 अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने की हकदार नहीं थी। विद्वान मजिस्ट्रेट का मानना था कि यद्यपि दोनों पक्षों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन न्यायिक पपृथक्करण की डिक्री आवेदन पर विचार करने में बाधा होगी और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि अधिनियम 2005 के तहत कोई घरेलू संबंध नहीं है और इसलिए, कोई राहत नहीं दी जा सकती है। यहां बताना आवश्यक हे कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष, अपीलकर्ता ने खुद के अलावा, तीन गवाहों के बयान कराये और पति ने डीडब्ल्यू -1 के रूप में खुद गवाह के रूप में उपस्थित हुआ। विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिका की विचारणीयता पर विचार करते समय गुण-दोष के संबंध में पक्षों की दलीलों को नोट किया था, लेकिन वास्तव में उस पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है।

7. पीड़ित पत्नी ने आपराधिक अपील संख्या 6(1)/2014 प्रस्तुत की, जिसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अगरतला ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए तय किया कि 2005 अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से पीड़ितों को तत्काल राहत देना है; इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य [1] में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के प्रावधान अधिनियम 2005 के तहत की गई कार्यवाही पर लागू होते है और इसलिए, आवेदन मियाद बाहर का होने से वर्जित हे। इस दृष्टिकोण से, अपीलीय अदालत ने अपील खारिज कर दी।

8. जिस पर एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने, जैसा कि आक्षेपित आदेश से पता चलता है, इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल (सुप्रा) के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि पत्नी ने आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत एक आपराधिक मामला वर्ष 2006 में दर्ज किया था और पति ने 2008 में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर ली थी, इसलिए, अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही

परिसीमन द्वारा वर्जित थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने एक तरह से यह विचार भी व्यक्त किया है कि अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं थी।

9. हमने अपने प्रारंभिक नोट में इस प्रकार के मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में बताया है। कानून के बारे में गलत धारणा हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम पाते हैं, न तो विद्वान मजिस्ट्रेट, न अपीलीय अदालत और न ही उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के रुख को समझने और उसकी सराहना करने का कोई प्रयास किया है। इस प्रकार के मामले और ऐसी अवस्था में इस न्यायालय तक नहीं आने चाहिए। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारी सुविचारित राय है कि यदि अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय अधिक सतर्क होते, तो पूरी संभावना होती कि गुणदोष के आधार पर निर्णय दिया जा सकता था। जो हुआ सो हुआ।

10. हमने "पक्षों की स्थिति", "न्यायिक पृथक्करण" और "स्त्रीधन के दावे" के संबंध में जो तथ्य गिनाए हैं, वे विवादित नहीं हैं। निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, अधिनियम 2005 की योजना की सराहना करना आवश्यक है। धारा 2(ए) "पीड़ित व्यक्ति" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है और जो प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है। धारा 2(एफ) "घरेलू संबंध" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या किसी भी समय एक साथ रहे हैं, जब कि वे सजातीयता, विवाह, या किसी रिश्ते के माध्यम से संबंधित रहे हैं या विवाह, गोद या संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य जैसे सम्बन्धों के रूप में एक साथ रह रहे हैं। धारा 2(जी) "घरेलू हिंसा" शब्द को परिभाषित करती है जिसे धारा 3 के समान ही अर्थ दिया गया है । धारा 3 की उपधारा (iv) "आर्थिक दुरुपयोग" से संबंधित है। जैसा कि मौजूदा तथ्यों में है, हम "आर्थिक दुरुपयोग" से चिंतित हैं, हम धारा 3(iv) को पुन: प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार है:-

"धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा.

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के तहत हकदार है, चाहे वह अदालत के किसी आदेश के तहत या अन्यथा संदेय हो जिनकी व्यथित, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू ज़रूरतें भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं है स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या अलग स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भटक का संदाय; से वंचित करना;

(ख) गृहस्थी की चीज़बस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, कीमती सामान, शेयर, प्रतिभूतियों, बांड और उसके सद्रश या अन्य संपत्ति का, जिसमें पीड़ित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके उपयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा सनयुक्तः या पृथकतः धारित किसी आँय संपत्ति का अन्य कोई संक्रामण; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुँच भी है, लगातार पहुँच के लिए प्रतिषेध या निबंधन।

स्पष्टीकरण ॥.- यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई का कोई कार्य, लोप, या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के तहत "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।"

11. धारा 8(1) राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है जितनी वह आवश्यक समझे और उस क्षेत्र या क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी अधिकार देती है जिसके भीतर एक संरक्षण अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिनियम 2005 द्वारा या उसके अंतर्गत उसे प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करेगा। प्रावधान, जैसा कि स्पष्ट है, अनिवार्य है और राज्य सरकार ऐसे संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है । धारा 12 मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन से संबंधित है। उपधारा (1) और (2) प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

"धारा 12 . मजिस्ट्रेट को आवेदन.-(1) एक पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु कि ऐसे आवेदन पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू हिंसा कि रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत मांगे गए अनुतोष वह अनुतोष भी भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा कि गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित कि गई क्षतियों के लिए प्रतीकार या

नुकसान के लिए वाद संस्थित के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है: परंतु जहां किसी अदालत द्वारा पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे या क्षति के रूप में किसी भी राशि की डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के तहत, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रव्रत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी।"

12. धारा 18 मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा आदेश पारित करने से संबंधित है। धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है और धारा 20 मौद्रिक राहत से संबंधित है। धारा 28 प्रक्रिया से संबंधित है और यह निर्धारित करती है कि धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत सभी कार्यवाही और धारा 31 के तहत अपराध आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। धारा 36 बताती है कि अधिनियम 2005 के प्रावधान ततसमय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

13. अधिनियम 2005 की संरचना को स्कैन करने के बाद, अब हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें अधिनियम 2005 के प्रावधानों की विवेचना की गई है। वीडी भनोट बनाम सविता भनोट [2] में यह सवाल उठा कि क्या अधिनियम 2005 के प्रावधानों को उस घटना के संबंध में लागू किया जा सकता है जो उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी। ज्ञात हो कि उच्च

न्यायालय ने प्रतिवादी के इस रुख को खारिज कर दिया था कि यदि घटना 2005 अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी तो 2005 अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इससे निपटते समय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ-साथ अधिनियम 2005 की धारा 31 और 33 के प्रावधानों पर विचार करने और कथन की जांच करने के बाद कहा था कि अधिनियम 2005 के उद्देश्य और कारण में यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से संसद ने कुछ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम 2005 अधिनियमित किया था। परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों की शिकार महिलाओं को संविधान के तहत अधिकारों की गारंटी दी गई है, और उन्हें एक कुशल और शीघ्र सिविल उपचार प्रदान करना है और इसके अलावा 2005 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत याचिका तब भी पोषणीय है, जब कि भले ही घरेलू हिंसा के कृत्य उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए हों, इस तथ्य के बावजूद की अतीत में वह अपने पति के साथ साझा घर में रहती थी, लेकिन जिस समय यह अधिनियम लागू हुआ, तब उसके साथ नहीं रह रही है। उच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार बताते हुए उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की: -

> "हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि PWD अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक शिकायत पर गौर करते समय, धारा 18, 19 और 20 के तहत आदेश पारित करते समय PWD अधिनियम के लागू होने से पहले के पार्टियों के आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है। हमारे विचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय

ने भी सही माना है कि भले ही एक पत्नी, जो अतीत में एक घर साझा करती थी, लेकिन अधिनियम लागू होने पर अब ऐसा नहीं कर रही थी, फिर भी वह PWD अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्राप्त करने की हकदार होगी।"

14. सरस्वती बनाम बाबू [3] में दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने वीडी भनोट (सुप्रा) में निर्णय का उल्लेख करने के बाद सिद्धांत को दोहराया। उसमें यह कहा गया है:-

"हमारा विचार है कि प्रतिवादी पति का कृत्य स्पष्ट रूप से डीवीए, 2005 की धारा 3 के दायरे में आता है, जो "घरेलू हिंसा" को व्यापक शब्दों में परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि डीवीए, 2005 के लागू होने से पहले पक्षकारों के आचरण को आदेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी पति ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का पालन नहीं किया है। उसने अपीलकर्ता पत्नी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष गलत बयान देकर अदालत को भी गुमराह किया। अपीलकर्ता पत्नी जो कि 2000 से प्रताड़ित की जा रही है, डीवीए, 2005 की धारा 18 और 19 के तहत संरक्षण आदेश और निवास आदेश के साथ-साथ डीवीए, 2005 की धारा 20(1)(डी) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमत भरण-पोषण की हकदार है। इन राहतों के अलावा, वह प्रतिवादी पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई मानसिक यातना और भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए मुआवजे और क्षति की भी हकदार है। इसलिए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दी गई राहतों के

अलावा, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता पत्नी को प्रतिवादी पति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, प्रतिवादी को अपीलकर्ता पत्नी के पक्ष में 5,00,000 रुपये की सीमा तक मुआवजा और क्षति का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"

15. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, निचली अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल (सुप्रा) के फैसले का उल्लेख किया है। उक्त मामले को उसके तथ्यात्मक परिस्थितियों के तहत समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्माल [4] के फैसले का हवाला दिया था जिसमें इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत अभिव्यक्ति "घरेलू संबंध" और सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य [5] के फैसले पर विचार किया था और उक्त निर्णयों को बिना विवाह के लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों के रूप में प्रतिष्ठित किया। न्यायालय ने पहले के निर्णयों का विश्लेषण करते हुए कहा कि वैध विवाह के लिए अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अलावा जोड़े को खुद को जीवनसाथी के समान समाज के सामने रखना चाहिए। उक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग थे क्योंकि वे मामले बिना विवाह के लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित थे। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों ने शादी कर ली है और तलाक के लिए सिविल कोर्ट की डिक्री कायम है और इसके अलावा उक्त फैसले और डिक्री को अमान्य घोषित करने का मुकदमा अभी भी सक्षम अदालत के समक्ष विचाराधीन है। उस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:-

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी 2 की ओर से किया गया निवेदन कि सिविल कोर्ट द्वारा तलाक देने का निर्णय और डिक्री अमान्य है और वे पति बने रहेंगे और पत्नी, पर इस स्तर पर तब तक ध्यान नहीं दिया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी 2 द्वारा उक्त

फैसले और डिक्री दिनांक 20-3-2008 को शून्य घोषित करने के लिए दायर मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में नहीं हो जाता। इसे ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा दिए गए सबूतों, विशेष रूप से टेलीफोन कॉल के रिकॉर्ड, एक साथ शादी में शामिल होने की तस्वीरें और बच्चे की स्कूल डायरी में उनके हस्ताक्षरों पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक सिविल कोर्ट का फैसला और डिक्री मौजूद है। इसी आधार पर, उसके वकील ने यह तर्क दिया कि तलाक के फैसले के बाद भी, वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते रहे और इसलिए 2005 अधिनियम के तहत शिकायत कायम रखने योग्य है, इस स्तर पर स्वीकार करने लायक नहीं है।" [जोर दिया गया]

16. यह ध्यान देने योग्य है कि सीआरपीसी की धारा 468 के प्रावधान लागू होने के संबंध में पत्नी द्वारा एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था। परिसीमा के मुद्दे पर प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

"..... धारा 468 सीआरपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर, धारा 28 और 32 के प्रावधानों जिनहे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा नियम, 2006 के नियम 15(6), जो सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करते हैं, के साथ पढ़ा जाने पर यह नज़रिया कि शिकायत घटना की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर ही दर्ज की जा सकती है, अतिश्योक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। उक्त नज़रिये को जापानी साहू बनाम चंद्र शेखर मोहंती, (2007) 7 एससीसी 394 और नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा, (2011) 6 एससीसी 508 में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा सुदृढ़ किया गया है।"

17. जैसा कि प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय ने इसका उल्लेख किया है लेकिन वास्तव में इसका प्रचार नहीं किया गया है। वास्तव में, वर्तमान मामले में उक्त पहलू पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

18. मुख्य मुद्दा जिसे संबोधित किया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या न्यायिक पृथक्करण के आदेश के कारण अपीलकर्ता "पीड़ित व्यक्ति" नहीं रह गया है। एक बार जब तलाक की डिक्री पारित हो जाती है, तो पक्षकारों की स्थिति अलग हो जाती है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री होने पर ऐसा नहीं होता है। जीत सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने, हालांकि एक अलग संदर्भ में, न्यायिक पृथक्करण की अवधारणा की ओर ध्यान दिलाया और फैसला सुनाया कि न्यायिक पृथक्करण अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है। न्यायिक पृथक्करण का डिक्री या आदेश पक्षकारों को अलग-अलग रहने की अनुमति देता है। किसी भी पक्ष को दूसरे के साथ रहने की कोई बाध्यता नहीं होगी। विवाह से उत्पन्न होने वाले पारस्परिक अधिकार और दायित्व निलंबित हैं। हालाँकि, डिक्री विवाह को विच्छेद या विघटित नहीं करती है। यह मेल-मिलाप और समायोजन का अवसर प्रदान करता है। हालाँकि एक निश्चित अवधि के बाद न्यायिक पृथक्करण तलाक का आधार बन सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकार इस उपाय का सहारा लेने के लिए बाध्य नहीं हैं और पक्षकार जीवन भर पति-पत्नी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं।

19. इस संबंध में, हम हीराचंद श्रीनिवास मनगांवकर बनाम सुनंदा [7] में प्राधिकार का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें निर्धारण के लिए जो मुद्दा उठा था, वह यह था कि क्या पति द्वारा दायर विवाह को विघटित करने की मांग करते हुए दायर तलाक की याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1-ए)(आई) के तहत इस आधार पर राहत देने से इनकार किया जा सकता है कि वह अदालत के आदेश के बावजूद

अपनी पत्नी और बेटी के लिए गुजारा भत्ता देने में विफल रहा है। पति इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता था और उसने अपीलकर्ता की ओर से व्यभिचार के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष से अधिक की अवधि तक विवाह के पक्षों के बीच सहवास की बहाली नहीं हुई है। पत्नी का पक्ष यह था कि अपीलकर्ता अदालत के आदेश के अनुसार भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए पति द्वारा दायर तलाक की याचिका खारिज कर दी जाएगी क्योंकि वह राहत पाने के लिए अपनी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। हाई कोर्ट ने पत्नी की दलील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता की तलाक की मांग को खारिज कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1-ए) (आई) के तहत तलाक लेने की एकमात्र शर्त यह है कि न्यायिक पृथक्करण कि किसी कार्यवाही में, जिसमें दोनों पति-पत्नी पक्षकार हों, डिक्री पारित होने के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक विवाह के पक्षकारों के बीच सहवास की बहाली नहीं हुई हो। यह आग्रह किया गया कि यदि उक्त शर्त पूरी हो जाती है तो अदालत को तलाक की डिक्री पारित करना आवश्यक है। पत्नी की ओर से, उक्त दलीलों का इस आधार पर विरोध किया गया कि पति न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद भी लगातार व्यभिचार में जीवन यापन कर रहा है और पत्नी और बेटी का भरण-पोषण करने में उचित रूप से विफल रहा है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1-ए)(i) का विश्लेषण किया। 1955 के प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए और न्यायिक पृथक्करण के बारे में बोलते हुए, यह व्यक्त किया गया कि पत्नी द्वारा दायर याचिका पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद यह दोनों पति-पत्नी का

कर्तव्य था कि वे सहवास के लिए अपना योगदान दें। पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में कार्य करे और पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि पति के प्रति समर्पित पत्नी के रूप में कार्य करे। यदि न्यायिक पृथक्करण के आदेश के बाद सफल सहवास के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नी द्वारा ईमानदारी से योगदान करने की यह अवधारणा लागू होती है, तो यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पति, पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करने में विफल रहा। एक पति के रूप में इस प्रकार उसने अधिनियम की धारा 23 के अर्थ में "गलत" किया । इसलिए, अधिनियम की धारा 13 (1- ए) के तहत तलाक द्वारा विवाह को समाप्त करने की पति की प्रार्थना को अनुमति देने से इनकार करना उच्च न्यायालय के लिए उचित था ।

20. और, न्यायालय ने आगे इस प्रकार कहा:-

> "... डिक्री का प्रभाव यह है कि विवाह से उत्पन्न होने वाले कुछ पारस्परिक अधिकार और दायित्व निलंबित हैं और डिक्री में निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। न्यायिक पृथक्करण की डिक्री उस विवाह बंधन को विच्छेद या विघटित नहीं करती है, जो कि कायम है। यह जीवनसाथी को मेल-मिलाप और पुनः समायोजन का अवसर प्रदान करता है। डिक्री पार्टियों कि सुलह से ढह सकती है, ऐसी स्थिति में संबंधित पक्षों के अधिकार जो विवाह से निलंबित हो गए थे, बहाल हो जाते हैं। इसलिए यह धारणा कि धारा 10(2) याचिकाकर्ता को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार देती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रतिवादी के साथ सहवास के लिए कोई प्रयास नहीं किया है और यहां तक कि सहवास के किसी भी कदम को विफल करने के लिए कार्य भी किया है,

वैधानिक प्रावधानों की उचित व्याख्या से प्रवाहित नहीं हो सकती है। पुनरावृत्ती करते हुये यहां यह कहा जा सकता है कि अधिनियम का उद्देश्य और आशय पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध को बनाए रखना है, न कि ऐसे रिश्ते को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।"

21. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एक मुद्दा उठा कि क्या व्यभिचार का वैवाहिक अपराध न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दिए जाने पर ही समाप्त हो गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक नया तथ्य या परिस्थिति है जो "गलत" है जो पति द्वारा दावा की गई तलाक की कार्यवाही में राहत प्राप्त करने के रास्ते में एक प्रकार कि बाधा मानी जाएगी। बता दें कि बाई मणि बनाम जयंतीलाल दह्याभाई [8] में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और अभिनिर्धारित किया कि पति की ओर से व्यभिचार में रहना एक निरंतर वैवाहिक अपराध है, और यह केवल न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री पारित होने पर स्थिर या समाप्त नहीं होता है जो पति-पत्नी के विवाह से संबन्धित कुछ कर्तव्यों और दायित्वों को निलंबित करता है और वैवाहिक बंधन नहीं तोड़ते। इसन्यायालय ने फैसला सुनाया कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला कानून की सही स्थिति नहीं बताता है। न्यायालय ने सौंदराम्मल बनाम सुंदरा महालिंगा नादर [9] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत को मंजूरी दी, जिसमें एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया था कि जो पति पत्नी की मांग पर पारित डिक्री के बाद भी व्यभिचार में रहना जारी रखता है, वह तलाक की डिक्री की मांग वाली याचिका में सफल नहीं हो सकता और धारा 23(1)(ए) इस राहत पर रोक लगाती है।

22. उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी तलाक की डिक्री और न्यायिक पपृथक्करण की डिक्री के मध्य अंतर है; पहले वाले में, अवस्था का विच्छेद होता है और पक्षकार पति और पत्नी नहीं रहते हैं, जबकि बाद वाले में,पति और

पत्नी के बीच संबंध जारी रहते है और विधिक संबंध जारी रहते है क्योंकि इन्हें छिना नहीं गया है। इस प्रकार समझा गया कि, नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिस पर उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है कि पक्षकार न्यायिक रूप से अलग हो गए हैं, अतः अपीलार्थी पत्नी " पीड़ित व्यक्ति " नहीं रही है, पूरी तरह से अपोषणीय है।

23. अगला मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह मियाद का मुद्दा है। पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन में वह अपना स्त्रीधन वापस पाने का दावा कर रही थी। सर गूरूदास बनर्जी ने "हिन्दू लॉ ऑफ मैरिज एंड स्त्रीधन" में स्त्रीधन को सौदायिका के रूप में वर्णित किया है जो इस प्रकार है:-

> "सबसे पहले, उपहार द्वारा प्राप्त संपत्ति का मामला लें। स्नेही संबंधियों के उपहार, जिन्हें सौदायिका स्त्रीधन के नाम से जाना जाता है, एक महिला की पूर्ण संपत्ति का गठन करते हैं, जिसे अलग करने की उसके पास हर समय स्वतंत्र शक्ति होती है, और जिस पर उसके पति के पास केवल एक योग्य अधिकार होता है, अर्थात् संकट के समय उपयोग का अधिकार।"

24. ज्ञात हो कि उक्त पाठ्यांश को प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार और अन्य [10] में उद्धृत किया गया है। उक्त मामले में, बहुमत ने एनआर राघवाचार्य द्वारा "हिंदू कानून" और मेन के "हिंदू कानून पर ग्रंथ" में वर्णित स्त्रीधन का उल्लेख किया। न्यायालय ने शास्त्रीय ग्रंथों का विश्लेषण करने के बाद राय दी कि:-

> "इसलिए, यह स्पष्ट है कि आवरण के दौरान एक हिंदू विवाहित महिला की संपत्ति के स्त्रीधन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और असंदिग्ध है; वह ऐसी संपत्ति की पूर्ण मालिक है और अपनी इच्छानुसार किसी

भी तरीके से इसका सौदा कर सकती है - वह इसे पूरा खर्च कर सकती है या अपने पति को संदर्भित किए बिना उपहार या वसीयत द्वारा अपनी मर्जी से दे सकती है। आम तौर पर, पति को इसमें कोई अधिकार या हित नहीं होता है, एकमात्र अपवाद यह है कि अत्यधिक संकट के समय, जैसे अकाल, बीमारी या इसी तरह, पति इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन वह इसे या इसके मूल्य को बहाल करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अधिकार पूरी तरह से पति का व्यक्तिगत है और विवाह में उसके द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति के खिलाफ ऋण के लिए डिक्री के निष्पादन में भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।"

25. उक्त मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया:-

"... पति को कोई अधिकार दिए बिना स्त्रीधन का एक शुद्ध और सरल समर्पण, केवल अपने कब्जे में वस्तुओं को रखने के अलावा, उसे अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है। पत्नी द्वारा मांगे जाने पर उक्त वस्तुओं को वापस न करने का पति के पास कोई औचित्य नहीं है और न ही वह उक्त संपत्ति का उपयोग करके उस पर व्यवसाय के नुकसान का बोझ डाल सकता है, जबकि स्त्रीधन पर कब्ज़ा सौंपते समय पत्नी ने कभी इसका इरादा नहीं किया था। शिकायत में आरोपों पर, पति अपनी पत्नी की ओर से काम करने वाले एक शुद्ध और सरल संरक्षक से कम या ज्यादा नहीं है और यदि वह सौंपी गई संपत्ति को कहीं और या अलग-अलग उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करता है तो वह धारा 406 के तहत मुकदमा चलाने का स्पष्ट जोखिम लेता है।

आईपीसी. तर्क की समानता पर, यह स्पष्ट है कि पति, अपनी पत्नी के स्त्रीधन का केवल संरक्षक होने के नाते, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उसके संयुक्त कब्जे में है और इस प्रकार संपत्ति में संयुक्त हित प्राप्त करता है।"

26. उक्त मामले में दिए गए निर्णय को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नए सिरे से देखने के लिए भेजा गया था। तीन जजों की खंडपीठ रश्मी कुमार (श्रीमती) बनाम महेश कुमार भादा [11] ने उक्त मामले में मुद्दे पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि:-

"9. एक महिला की अपने पति के नियंत्रण से स्वतंत्र, निपटान की शक्ति, सौदायिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य संपत्तियों तक भी फैली हुई है। देवला कहते हैं: "एक महिला का रखरखाव (वृत्ति), आभूषण, अनुलाभ (सुल्का), लाभ (लाभ), उसकी स्त्रीधन हैं। उसे स्वयं इसका आनंद लेने का विशेष अधिकार है। उसके पति को संकट के अलावा इसका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है...।" हिंदू कानून के प्रसिद्ध प्रोफेसरों में से एक, प्रो. एस. वेंकटरमन द्वारा संपादित एनआर राघवाचार्य के हिंदू कानून - सिद्धांत और उदाहरण, (8 वां संस्करण) में पैरा 468 "स्त्रीधन की परिभाषा" से संबंधित है। पैरा 469 में "अधिग्रहण के स्रोत" से संबंधित यह कहा गया है कि एक महिला के कब्जे में संपत्ति के अधिग्रहण के स्रोत हैं: शादी से पहले उपहार, शादी के उपहार, शादी के बाद उपहार आदि। पैरा 470 "युवती को उपहार" से संबंधित है। पैरा 471 "शादी के उपहार" से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि शादी के समय दुल्हन को उपहार में दी गई संपत्ति, चाहे रिश्तेदारों या अजनबियों द्वारा, अधियाग्नि या आध्यावाहनिका, दुल्हन का स्त्रीधन है। पृष्ठ 426 पर पैरा 481 में, यह

कहा गया है कि दुल्हन को उसके पति या पिता द्वारा दिए गए आभूषण उसकी स्त्रीधन संपत्ति का गठन करते हैं। पैरा 487 में "छिपाने के दौरान शक्तियां" से संबंधित यह कहा गया है कि सौदायिका का अर्थ है स्नेही रिश्तेदारों का उपहार, इसमें यौताका या विवाह के समय प्राप्त उपहार के साथ-साथ इसका विपरीत अयुताका दोनों शामिल हैं। ऐसी संपत्ति के संबंध में, चाहे वह उपहार द्वारा दी गई हो या वसीयत द्वारा दी गई हो, वह पूर्ण मालिक है और अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से इसका सौदा कर सकती है। वह इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है, बेच सकती है या दे सकती है।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह से पहले, विवाह के समय या विदाई के समय या उसके बाद उसे उपहार में दी गई संपत्तियां उसकी स्त्रीधन संपत्तियां हैं। यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और उसे अपनी मर्जी से इसका निपटान करने का पूरा अधिकार है। उसकी स्त्रीधन संपत्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। पति अपने संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को इसका मूल्य लौटाए। इसलिए, स्त्रीधन संपत्ति पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई शीर्षक या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता है।"

27. इतना कहने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्त्रीधन संपत्ति पत्नी की विशेष संपत्ति है, यह सबूत दे देने पर कि उसने संपत्ति सुपुर्द कि है या स्त्रीधन संपत्ति पर प्रभुत्व अपने पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य को सौंपा है, यह स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई और विशेष समझौता से संपत्ति पति

या परिवार के अन्य सदस्य को दी गई थी। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले में यह हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है कि जब पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया या वहां से बाहर निकाल दिया गया तो संपत्ति पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य को कैसे सौंपी गई। इसके बाद, न्यायालय ने सौंपने की अवधारणा की ओर रुख किया और अंततः प्रतिभा रानी (सुप्रा) के मामले में इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह एक सतत अपराध है और क्या यह प्रतिदिन चल सकता है, इसकी प्रासंगिकता उक्त मामले में खत्म हो गई है, क्योंकि अदालत ने जांच के बाद पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात के अपराध की दी गई शिकायत समय सीमा के भीतर थी ।

28. स्त्रीधन की अवधारणा की सराहना करने के बाद, अब हम "कार्रवाई के सतत कारण" के अर्थ पर आगे बढ़ेंगे। राजा बहादुर सिंह बनाम भविष्य निधि निरीक्षक और अन्य में[12] न्यायालय ने निरंतर अपराध से निपटते समय राय दी कि अभिव्यक्ति "निरंतर अपराध" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन अभिव्यक्तियों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है या स्थैतिक आयात नहीं है, को परिभाषित करना कठिन है। न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी [13] में पहले के फैसले का हवाला दिया और उसी से एक अंश दोहराया जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है: -

> "एक निरंतर अपराध वह है जो निरंतरता के लिए अतिसंवेदनशील है और जो एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है उससे अलग होता है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या उसकी आवश्यकता का पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें जुर्माना शामिल होता है, जिसका दायित्व तब तक जारी रहता

है जब तक कि नियम या उसकी आवश्यकता का पालन या अनुपालन नहीं किया जाता है। प्रत्येक अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और दोबारा होता है, तो अपराध किया जाता है। दो प्रकार के अपराधों के बीच अंतर एक कार्य या चूक के बीच है जो एक बार और सभी के लिए अपराध बनता है और एक कार्य या चूक जो जारी रहती है, और इसलिए, हर बार या अवसर पर एक नया अपराध बनता है जिस पर यह निरंतर जारी रहता है। इस प्रकार निरंतर अपराध के मामले में, अपराध जारी रहने का घटक होता है जो कोई कार्य या चूक सिर्फ एक बार करने के किसी अपराध के मामले में अनुपस्थित होता है।"

29. न्यायालय ने आगे कहा:-

"इस अनुच्छेद से पता चलता है कि यह कहने के अलावा कि एक निरंतर अपराध वह है जो जारी रहता है और एक गैर-निरंतर अपराध वह है जो सिर्फ एक बार के लिए किया जाता है, न्यायालय को निरंतर अपराध को समझाना मुश्किल हो गया। उस कठिनाई को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि कुछ उदाहरणात्मक मामले निरंतर अपराध और गैर-निरंतर अपराध के बीच अंतर को सामने लाने में मदद करेंगे। न्यायालय द्वारा संदर्भित उदाहरणात्मक मामले तीन इंग्लैंड से, दो बॉम्बे से और एक बिहार से हैं।"

30. इसके बाद, न्यायालय ने प्राधिकारियों को संदर्भित किया और देवकरण नेन्शी (सुप्रा) की ओर रुख किया और अंततः कहा:-

"यह सवाल कि क्या कोई विशेष अपराध एक सतत अपराध है, आवश्यक रूप से उस कानून की भाषा पर निर्भर होना चाहिए जो उस अपराध को बनाता है, अपराध की प्रकृति और सबसे ऊपर, उस उद्देश्य पर जो उक्त कृत्य विशेष को अपराध के रूप में गठित करके प्राप्त करने का इरादा रखता है ..."

31. कानून के उपरोक्त कथन के संबंध में, हमें यह देखना होगा कि पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा स्त्रीधन को अपने पास रखना एक निरंतर अपराध है या नहीं। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि पत्नी स्त्रीधन की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन यह उसे आपराधिक विश्वासघात के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकता है। हमें बताना होगा कि अधिनियम 2005 लागू होने से पहले यही स्थिति थी। 2005 के अधिनियम में, "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा स्पष्ट रूप से किसी भी महिला की स्थिति के बारे में बताती है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। "आर्थिक दुरुपयोग" का दायरा बहुत बड़ा है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3(iv) में परिभाषित किया गया है। धारा 12, जिसका प्रासंगिक भाग यहां पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल (सुप्रा) में यह माना गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498, 2005 के अधिनियम के तहत उक्त मामले पर लागू होती है, जैसा कि संरक्षण के नियम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा नियम, 2006 के 15(6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 28 और 32 के तहत परिकल्पित है। हमें इसका उल्लेस्ख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बनी रहती है और स्त्रीधन पति के संरक्षण में रहता है, पत्नी हमेशा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत दावा कर सकती है। हम ऐसा सोचने के लिए प्रवृत्त हैं क्योंकि

विवाह विच्छेद के आदेश के कारण पक्षों के बीच की स्थिति विच्छेद नहीं होती है। "निरंतर अपराध" की अवधारणा स्त्रीधन से वंचित होने की तारीख से आकर्षित होती है, क्योंकि न तो पति और न ही परिवार के किसी अन्य सदस्य का स्त्रीधन पर कोई अधिकार हो सकता है और वे संरक्षक बने रहते हैं। अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए, वह अधिनियम 2005 के तहत एक या अधिक राहतों के लिए संरक्षण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। वर्तमान मामले में, पत्नी ने 22.05.2010 को आवेदन प्रस्तुत किया था और उक्त प्राधिकारी ने इसे 01.06.2010 को अग्रेषित किया था। आवेदन में पत्नी ने उल्लेख किया था कि पति ने जनवरी 2010 से मासिक भरण-पोषण का भुगतान बंद कर दिया है और इसलिए, वह स्त्रीधन के लिए आवेदन दायर करने के लिए मजबूर हुई है। "अपराध जारी रखने" की उक्त अवधारणा और की गई मांगों के संबंध में, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था और नीचे की अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आवेदन को मियाद बाहर का होना कह कर खारिज करके एक गंभीर त्रुटि की है।

32. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय और निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। मामला गुण-दोष के आधार पर 2005 अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन पर आगे बढ़ने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता शाहिद पठान द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।